SHRIMATI MARGARET ALVA: Sir, the rivers are not polluting. The rivers are being polluted.

SHRI NILAMANI RAUTRAY: The discharge from industries and other things are also polluting the rivers. A Central Authority is absolutely necessary to take care of these rivers and to chalk out a programme for that and that also is under our active consideration. For that, money is also required and we are looking up to the Planning Commission to see to it if our ideas can be translated into action in controlling this pollution.

SHRI SARADA MOHANTY: Sir, I want to know what the progress of Ganga Action Plan is so far.

SHRI NILAMANI ROUTRAY: Sir, under the Ganga Action Plan, 262 schemes are under execution. Out of these 262 schemes, in Bihar it is 35, in West Bengal it is 110 and in Uttar Pradesh it is 107. For all these schemes there is an allocation of Rs. 284 crores.

Out of these 262 projects, 152 have been completed and others are under way.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : सभापति महोदय, प्रश्न मेरे साथी ने रख दिया है, उसका दूसरा हिस्सा पूछ लेता हूं, गंगा प्लान का। गंगा के साथ जमुना भी मिलने के बाद गंगा बन जाती है, तो क्या जमुना को शुद्ध रखने के लिए भी कोई कार्यवाही की जा रही है। और जो आपका नेशनल रावर आथारिटी है, क्या गंगा एक्शन प्लान इस आथारिटी के नीचे आ जाएगा या अलग रहेगा।

श्री चतुरानन मिश्र : गंगा तो अशुद्ध हो ही नहीं सकती।

श्री सभापति : चतुरानन जी, जब आप मंत्री बन तब जवाब दीजिएगा।

श्री चतुरानन मिश्र : गंगा कभी अशुद्ध हो ही नहीं सकती।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : यह धार्मिक मान्यता की बात है कि गंगा कभी मैली नहीं हो सकती। गंगा कभी अशुद्ध नहीं हो सकती।

श्री चतुरानन मिश्र : लेकिन आप गंगा को अशुद्ध कहने लगे... (**व्यवधान**)

श्री अटल बिहारी वाजपयी : कलयुग में गंगा अशुद्ध हो सकती है।

श्री चतुरानन मिश्र : गंगा हो अशुद्ध नहीं सकती है, बाकी सब अशुद्ध हो सकता है। शास्त्र का नियम है।

श्री सभापति : अब यह छोड़िए। His question is very simple. There is already a plan under operation for cleaning the Ganga. There is an authority for that purpose. Will that authority come under this authority or will it remain separate?

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : श्रीमन, मेरा सवाल यह है कि जमुना नदी भी गंगा में मिलती है तो क्या उसके पानी को साफ करना भी इसमें सम्मिलित है?

MR. CHAIRMAN: The Ganga cleaning process does not include cleaning the Jamuna because it is the main tributary of the Ganga.

SHRI NILAMANI ROUTRAY: As I understand the honourable Member, he wants to know whether the Jamuna is also included in the Ganga Action Plan. So far it is not included. But it is the intention of the Ganga Authority to include the Jamuna river also because cleaning of the Ganga is not possible without cleaning the Jamuna. And then, it also depends upon funds.

National Sports Policy

*363. SHRI S. S. AHLUWALIA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government are contemplating to review the National Sports policy;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether Government propose to get the Constitution (Sixty First Amendment) Bill, 1988 relating to sports which is pending in Rajya Sabha, passed during the current session; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCECS DEVELOPMENT (SHRI CHIMANBHAI MEHTA): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) No, Sir.

(d) Government are in the process of consultation with the State Governments again in this regard.

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया: सभापति महोदय, जवाब तो बड़े ही अच्छे जाए हैं—नो सर, नो सर, डज नॉट एराइज। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार स्पोर्टस फैडरेशन और स्टेट गवर्नमेंट्स से इससे पहले भी कोई वार्तालाप कर चुकी है या करने जा रही है? इससे वे किस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं यह बताने की कृपा करें। इससे पहले कितने राज्य इस बिल को स्वीकृति दे चुके हैं? उन राज्यों की संख्या कितनी है और वे कौन-कौन से राज्य हैं?

श्री चिमनभाई मेहता : महोदय, स्पोर्टस पालिसी बनने से पहले 4 वर्षों तक स्पोर्टस फरेशन, स्टेट गवर्नमेंट्स और स्पोर्टस मिनिस्टर्स आफ दि स्टेटस से वार्तालाप हुआ था और उसके बाद ही स्पोर्टस पालिसी बनी थी। इसलिए हमने कहा—नो सर, क्योंकि हम फिलहाल इसे रिवाइज नहीं कर रहे हैं चूंकि पहले ही बहुत अच्छी तरह से वाईटल स्केल पर। इस पर इन्सैडप्स डेलीबेरेशन हुई थी

अब माननीय सदस्य ने बिल के बारे में पूछा है तो 24 राज्यों ने उसके बारे में जवाब भेजा है। उनमें से कुछ स्टेट्स हैं जिन्होंने कहा है कि हम ऐसा बिल चाहते हैं, कन्करेंट लिस्ट में इस सब्जैक्ट को लाने की बात है और कुछ राज्यों ने उसके बारे में इंकार कर दिया है। इसलिए हमने सोचा है कि अगर बिल लाना हो तो दोबारा कंसल्टेशन्स करने की आवश्यकता होगी।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया: सभापति महोदय, यह जो राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार के बीच लड़ाई चलती रहती है कि स्पोर्टस राज्य सरकार का विषय है या केन्द्रीय सरकार का विषय है, इस लड़ाई के चक्कर में हम आज तक गोल्ड-मैडलों की संख्या नहीं बढ़ा सके ... **(व्यवधान)**

डा० जी० विजय मोहन रेड्डी: लड़ाई किधर है?

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया: लड़ाई तो चल रही है। अभी लड़ाई देखो। ... **(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य: हमारे मंडल कमीशन का क्या हुआ?

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : वह तो मंडल कमीशन है।

श्री सभापति : क्या मंडल कमीशन ने स्पोर्टस के बारे में भी कुछ कहा है?

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया: : नहीं सर, अभी तो मंडल कमीशन को लेकर राज्य सरकारों में ही लड़ाई चल रही है। अभी यह मंडल बनेगा, घबराइए मत। ... **(व्यवधान)** सभापति महोदय, मेरा सीधा सवाल यह है कि मैं पीछे अखबारों में पढ़ रहा था कि ईस्ट और वेस्ट जर्मनी के यूनिफिकेशन के बाद सारी वर्ल्ड को अपेक्षा है कि सारे गोल्ड मैडल वही ले जाएंगे....

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: थ्रेट क्या है ?

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया: बार्डर पर नहीं स्पोर्टसमैन को थ्रेट है। मेरा सवाल है कि आज तक जो कुछ हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए क्या सरकार स्कूलों और कालेजों में...

श्री चतुरानन मिश्र: भारत गोल्ड लेता ही नहीं है तो खतरा कहां है ?...

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया: यही तो मैंने पहले कहा। आप आधी बात तो सुनते ही नहीं। पहले मेरी बात सुनिए। मेरा सीधा प्रश्न है कि क्या सरकार स्कूलों और कालेजों में इनफ्रास्ट-क्चर तैयार करेंगी ? मैं खासकर उन ट्रायबल इलाकों की बात करता हूं जैसे बिहार, उड़ीसा, बंगाल, मध्य प्रदेश के ट्रायबल एरियाज में युवकों में काफी शक्ति है कि वे इन खेलों में पार्टिसिपेट करें। आपने ट्रेनिंग सेंटर सब जगह खोले हैं लेकिन इन इलाकों में ट्रेनिंग सेंटर नहीं खोले हैं। तो क्या इन इलाकों में ट्रेनिंग सेंटर खोलने की व्यवस्था करेंगे, यह जवाब दें।

श्री चिमनभाई मेहता: सभापति महोदया, हमने स्कूलों और कालेजों में इसको बढ़ाने के लिए जो स्पोर्टस पालिसी बनी उसमें इसका जिक्र किया है कि फिजिकल एजुकेशन स्कूल-कालेजों के विषयों में, करिकुलम में रखी जानी चाहिए। लेकिन काफी हद तक स्कूल-कालेज स्टेट्स के जुरिस्डिक्शन में आते हैं। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके लिए कोई स्पेशल सुविधा कर पाए या नहीं, उसके बारे में काफी सोच विचार हो रहा है और 7वीं योजना में 200 करोड़ का प्रावधान उनके लिए किया गया था, हमने इस बार वर्किंग ग्रुप ने यह प्रावधान 680 करोड़ स्पोर्टस के लिए प्रोजेक्ट किया है। तो उसका इस्तेमाल सब चीजों में होगा। जो ट्रायबल एरियाज हैं उनमें आरचरी के बारे में...

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया: आरचरी के बारे में ही नहीं, सभी चीजों के बारे में, कुश्ती के बारे में, अन्य चीजों के बारे में आप ट्रायबल इलाकों में ट्रायबल इलाका में सेंटर खोलेंगे या नहीं ?

श्री चिमन भाई मेहता: वे भी स्टेटस एरिया में आते हैं। उनके लिए हमने पहले की अपेक्षा 200 करोड़ से राशि बढ़ाकर 680 करोड़ तक जाने की दरख्वास्त की है, जिस पर सोच-विचार बड़े सक्रिय रूप से हो रहा है।

MR. CHAIRMAN: Yes, Mr. Suresh Kalmadi.

SHRI SURESH KALMADI: Sir, I would like to ask the Minister one thing since the Deputy Minister of Sports is not here today. He has gone on record to say that after the Asian Games in Beijing, there will be a review of the National sports policy. He has gone on record more than once and I do not know how the Minister has said that there is going to be no review at all.

In this connection, I would like to ask the Minister whether they are going to have a dialogue with the concerned people on the role of the Government, on role of the Sports Authority of India and the role of the sports federations. Now, there is too much of overlapping. Therefore, my question is whether you are going to have a dialogue with the various bodies and come to an agreement on certain aspects.

Also, I would like to know whether the Government intends to review the guidelines which were there earlier—most of the guidelines are good—because the federations have been objecting to certain of them, especially the ones regarding the selection process. Therefore, I would like to know whether you intend to review them.

Finally, with regard to the Constitutional amendment which had come up last time, most of the federations have said that they were never consulted. Maybe you have to consult the State Governments also. So, I would like to know whether you intend consulting them also before you take up the amendment Bill.

SHRI CHIMANBHAI MEHTA: Sir, I do not know about what has appeared in the Press. But we are having a liscussion on the sports policy regularly and, recently also, last month, with eminent sportsmen of the entire country, we had a discussion and we had a discussion with the awardees, with the journalists and with the authorities concerned. So it was being discussed. Now, about the guidelines about which they are talking, certain Federations are not accepting those guidelines. This can be discussed with them, what they do not accept. The Constitutional Bill should be discussed with the Federations. First, let the States be consulted. Therefore, we have nothing against consulting the Federations. But ultimately the States have to be consulted.

SHRI SURESH KALMADI: There is a big clause on Federations in the Bill. You must have a dialogue with the Federations.

MR. CHAIRMAN: He is consulting the States. Then he will think of Federations. Shri Kamal Morarka.

SHRI KAMAL MORARKA: Sir, the Minister has replied that there has been no change in the sports policy. My specific question to the Minister is that actually a change is required and Mr. Suresh Kalmadi has very rightly pointed out that the Government wanted to arm itself with powers to interefere with the autonomous Federations. Sir, I would like to have an assurance from the Minister that this provision will be dropped Sir, the time has come and the Government should make it clear that sports will be autonomous and the Goveernment will not interfere. In the Beijing games we have a funny spectacle, sorry spectacle, the Indian contingent, parallel contingents being announced. I think it is a very sad state of affairs. I want a specific assurance from the Minister that the Government will stop interfering in sports matters and allow the Sports Federations to function so that there is as confusion. Confusion has come because the Government in a hurry has recognized the rebel section of the IOA, without going fully into the matter. The matter is in the court.

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: Led by Mr. Shukla.

SHRI KAMAL MORARKA: I am not concerned with personality.

SHRI DIGVIJAY SINGH: Mrs. Margaret Alva did the same thing earlier. It was Mrs. Alva who initiated politics into sports. (*Interruptions*)

SHRI CHIMANBHAI MEHTA: It is our policy and also our practice not to interfere in the autonomy. But about the reference that is made the matters are *sub judice* and therefore I would not be able to say beyond a certain thing. But certain orders of the courts have come in between. If you permit me, I will read out the court's orders... (*Interruptions*)

AN HON. MEMBER: That is not required.

SHRI KAMAL MORARKA: But if the matters are *sub judice*, why has the Government given recognition to one faction. It is a simple matter. Let him say that the matter is *sub judice* and Government will not interefere. I am happy.

SHRI CHIMANBHAI MEHTA: Therefore, the courts' orders have to be read, because they are the proper authority. The Madhya Pradesh High Court order of June 29 says... (*Interruptions*) There are three orders from three courts. It says that a prima facie case appeas to have been made for maintaiing *status quo* confered upon Respondent No. 4.

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: It is something else. (*Interruptions*)

SHRI SURESH KALMADI: The matter is in the Supreme Court tomorrow.

SHRI CHIMANBHAI MEHTA: The Madras High Court bench also....

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: No... (Interruptions)

SHRI CHIMANBHAI MEHTA: When the matter is sub judice. I do not interfere... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: I cannot answer on his behalf. He said that the matter is *sub judice.* (*Interruptions*)

If you have any grievance, you talk to him separately. This is not the forum. Kumari Chandrika Kenia.

KUMARI CHANDRIKA PREMJI KENIA: Sir, it is a welcome step by the Government to augment the funds allotted to the Sports Department. The hon. Minister has now stated that in the Five Year Plan they increased the allotment to Rs. 689 crores. I would like to ask two or three pertinent questions. I must remind the hon. Members here, Sir, that I have been a sportswoman; I have played for the country for more than 10-15 years in different sports. My question is pertaining to Bombay. I was born and brought up in Bombay. And I find there are not sufficient facilities available in Bombay. One thing we wanted was proper fund for children's activities. Mrs. Margaret Alva knows about it. Secondly, we neet an indoor stadium in Bombay. There is a zonal centre to be set up in Aurangabad for the West Zone and two crores of rupees are to be allotted for that Zonal Sports Complex.. I would like to know from the hon. Minister whether the allotment of this money can be made immediately.

Secondly, Mr. Suresh Kalmadi has spoken about the promotion of sports. Sports Federation and the national policy on sports. My suggestion will be that we need a supervisory committee comprising ex-players, coaches and trainers who will supervise the Federation because the officers are not concerned with sports. These are the two questions on which I would like to have answers from the hon. Minister.

SHRI CHIMANBHAI MEHTA: About certain provisions to be made for the projects in Aurangabad and Bombay in Maharashtra, I would say that these are questions of detail. I would request the hon. Member to discuss them with me. We will certainly do as much as can be done.

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV: The sports complex at Aurangabad has already been accepted by the Government. (*Interruptions*)

SHRI CHIMANBHAI MEHTA: There are certain disputes about the Federations as to who would supervise them. That question is a separate question. That can be looked into afterwards.

SHRI SIKANDER BAKHT: Do you agree, Mr. Minister, that our performance in the area of sports is getting poorer by the day? How long does the hon. Minister wish to wait for the consultations which he has referred to just now? Secondly, we are in a mess as far as sports management is concerned. What steps have been taken especially in view of the ASIAD which has practically arrived? Non-interference by Government in the affairs of the sports management is a regulation of the Olympic Charter. What steps are being taken to ensure that the sickness of the Sports Federation and Associations is not transferred to the sports personnel?

SHRI CHIMANBHAI MEHTA: About the consultation process which the hon. Member is asking, I have already said that we are again going to ask for the comments of the States. Now the composition of the Parliament and the States has changed. We would be too happy if better reactions follow. We have suggested to bring sports in the Concurrent List.

About non-interference, we are committed to that policy. Sir, the question arises all of a sudden in

view of the Beijing games. I am not referring to a sub judice matter.

SHRI SIKANDER BAKHT: That part of the question does not arise. I concede the fact that the Government cannot interfere in sports management. What I am saying is that the sickness of sports management bodies is being transferred to the players themselves and the players are becoming sick and diseased. A diseased player can never perform. What are you going to do about it?

SHRI CHIMANBHAI MEHTA: This is a very serious observation. We will inform the managements that this is the impression of the hon. Members and we would like to get their response.

Pesticides for use in forestry

*363A. SHRI B. K. HARIPRASAD: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether a list of pesticides for use in forestry has been prepared on the U.K. Model and if so, the details thereof; and

(b) if not, the reasons therefor and corrective action to be taken in this regard?

THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI NILAMANI ROUTRAY): (a) and (b) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) List of pesticides for use in forestry on the basis of U.K. Model has not been prepared by Government of India. However, a list of insecticides being commonly used to control insect pests and diseases in *forest nurseries and plantations has* been prepared by Forest Research Institute, Dehra Dun. Details are given in the enclosed Annexure.

ANNEXURE

Commonly used Insecticides in Forestry

Sl. No.	Name of Insecticide
1.	Aldrin 30 E.C.
2.	Aldrin 10% dust
3.	Lindane 20 E.C.
4.	Endosulphan 35 E.C.
5.	Thimet
6.	Dimacron
7.	Monocrotphos
8.	Rogar
9.	Malathion
10.	Fenitmothion
11.	Chlorpyriphos
12.	Dichloryas
13	Fenthron
14.	Anthoo
15	Zolone